पटना-बाढ़-सुरक्षा तटबन्ध योजना

*177. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और बिहार सरकार के इंजीनियरों ने मिलकर 'पटना-बाढ़-सुरक्षा-तटबन्ध' की योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च होगी और भारत सरकार ने उसमें से कितनी राशि बिहार सरकार को दी है ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने उस अनुमानित राशि को बढ़ा दिया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) । (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(क) पटना बाढ़ सुरक्षा स्कीम बिहार राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1975 में पटना में आई बाढ़ों सम्बन्धी उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई थी। बिहार सरकार के द्वारा गठित की गई इस समिति में केन्द्र तथा राज्य सरकार के सदस्य तथा बिहार के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वाले व्यक्ति सदस्य थे। (ख) सभी तफ़नीकी आंकड़ों को एकत्र करने के बाद तैयार की गई विस्तृत स्कीमों के अभाव में, विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में लगभग 1068 करोड़ रुपये के निर्माण-कार्यों का ही उल्लेख किया था।

पटना बाढ़-सुरक्षा कार्यों के लिए भारत सरकार ने केवल 1975-76 के लिए 2.65 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता मंजूर की थी। इस प्रयोजन के लिए राज्य की 1976-77 की वार्षिक योजना के लिए 8 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) उन निर्माण-कार्यों के लिए, जो हाथ में लिए गए हैं, बिहार सरकार द्वारा तैयार किए गए विस्तृत अनुमानों में पटना सुरक्षा स्कीम कार्यों के लिए 17.2 करोड़ रुपए की लागत दर्शायी गई है : विस्तृत अनुमान वास्तविक स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित हैं और सभी सम्बन्धित तकनीकी आंकड़ों को एकत्रित करने और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद तैयार किए गए हैं।

अतिरिक्त धन की आवश्यकता अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक तथा विस्तृत लागत अनुमान लगाने, तथा उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट में और संशोधनों की सिफारिशें करने, सुरक्षा सम्बन्धी चिनाई कार्यों तथा रिवेटमेंट की लम्बाई तथा ऊंचाई में वृद्धि हो जाने, जल विकास नालियों की संख्या और लम्बाई में वृद्धि हो जाने और अधिक पंपिंग स्टेशनों इत्यादि की व्यवस्था किए जाने के कारण हुई है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पटना बाढ़ सुरक्षा योजना के बारे में जो वक्तव्य प्रश्न से सम्बन्धित किया गया है इस में प्रारम्भिक बात यह बतलाई गई है कि पूरे बांध को बनाने में लगभग 11 करोड़ रुपये खर्च होंगे, अब जो नया एटीमेट वहां की सरकार ने इन के इंजीनियरों की राय से या मदद से बनाया है वह 17 करोड़, से ज्यादा है। मैं स्वयं कई दफा इस बांध को देख आया हूं और आप को भी इसे देखने का मौका मिला

होगा क्योंकि यह बांध आप के क्षेत्र में भी पड़ता है, वहां बहुत सी गड़बड़ियां मैं ने देखीं, तो क्या आप को इस बात की कोई शिकायत मिली है कि बांध के निर्माण के सिलसिले में तरह तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सीमेंट वगैरह खुलेआम बेचे जा रहे हैं? अगर इस तरह की कोई जानकारी हो तो सदन को बताएं और उस को रोकने के लिए कौन सी कार्यवाही आज कर रहे हैं यह भी बताने का कष्ट करें। साथ ही अगर आप उसे पक्का बनवाते पूरे बांध को, कच्चे में तो 17 करोड़ से ज्यादा वहां दिया, पक्का बनवाते तो आप का कितना व्यय होता?

श्री केदार नाथ सिंह। अध्यक्ष महोदय, पहले तो शास्त्री जी को गलतफहमी है कि बिहार के इंजीनियरों ने उस के एस्टीमेट को बढा दिया। जो ओरिजिनल एस्टीमेट था वह बिहार गवर्नमेंट ने जो एक कमेटी बनाई थी उसकी इंटेरिम रिपोर्ट के हिसाब से जो उन्होंने आंकड़े बनाए उस से वह 10 करोड़ रुपये होता था। लेकिन जब उस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई उसके बाद इंजीनियर्स ने बैठ कर उसको बनाया, और तब 17.2 करोड़ का प्लान हुआ।

जहां तक भ्रष्टाचार के बारे में कहा है, आपका ही एक पत्र हम को मिला है और उस पत्र को हमने अधिकारियों को दे दिया जिसपर जांच हो रही है।

MR. SPEAKER: Now, the Question Hour is over.

WITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Memorandum on Protection to Onion Producers

*165. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Government have received any memorandum from the Nasik District Kisan Sabha, Nasik-1 (Maharashtra) dated the 13th April, 1976 regarding protection to onion producer; and

(b) reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) The Memorandum from Nasik District Kisan Sabha has been received in the Ministry of Agriculture and Irrigation on 19th August, 1976.

(b) The points raised in the Memorandum will be examined in the light of overall policy governing marketing and exports of onion.

Allotment for Construction of Godowns by F.C.I. during 1976-77

*168. SHRI K. SURYANARAYANA: will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has made a separate allotment for construction of new godowns by the Food Corporation of India in 1976-77;

(b) if so, the allotment made; and

(c) the action taken for construction of the godowns?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) and (b). A